**शीर्षक: दक्षेस शिखर सम्मेलन और भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले हालिया घटनाक्रमों के संबंध में कोलंबो की अपनी हाल ही की यात्रा पर एक वक्तव्य दिया।**

**पूर्वाह्न 11.14 बजे**

**प्रधानमंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी):** महोदय, पिछले कुछ सप्ताहों से, सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और हमारी विदेश नीति में हो रहे बदलावों के बारे में सभा को नियमित रूप से सूचित किया है। इस अवसर पर मैं माननीय सदस्यों को हाल की घटनाओं और की गई बातचीत के बारे में अद्यतन जानकारी देना चाहता हूँ।

मैंने 28-31 जुलाई, 1998 को कोलंबो का दौरा किया और 10वें योजना आयोग की बैठक में भाग लिया तथा विदेश मंत्री के रूप में शिखर सम्मेलन से पूर्व, मंत्रीस्तरीय बैठक में शिष्टमण्डल का नेतृत्व किया जो क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के बारे में थी। हमारे इस विचार के साथ सबकी आम सहमति थी कि बदली हुई वैश्विक आर्थिक स्थिति से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करना और इस अवसर का लाभ उठाना आवश्यक है। शिखर सम्मेलन के दौरान इसी बात पर चर्चा की गई।

मुक्त व्यापार क्षेत्र; कम विकसित देशों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, उदारीकृत व्यापार और उसे सुगम बनाने के उपायों सहित, इस प्रयोजन हेतु एक व्यापक कानूनी ढांचा तैयार करने के विषय पर बातचीत करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया जाएगा। दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौते के अंतर्गत, व्यापार वार्ताओं के तीसरे दौर को संपन्न करने और अगले दौर की वार्ता शुरू करने के लिए समानांतर कदम उठाए जाएंगे।

हमने व्यापार उदारीकरण को गति देने के लिए साहसिक पहलों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और तत्परता दोहराई है। इस क्षेत्र के हित में, दूरगामी, सकारात्मक, आर्थिक और विकासात्मक परिणामों को ध्यान में रखते हुए मैंने विशेष रूप से आयात पर सभी मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाने के अपनी सरकार के निर्णय की घोषणा की थी और इस निर्णय स्वागत किया गया। हमने इस बात की भी जानकारी दी कि हम इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं।

हमारी चर्चा में, इस विचार को मान्यता मिली कि व्यापार संबंधी संयुक्त उद्यमों, निवेश और पर्यटन जैसी सेवाओं में व्यापार के माध्यम से व्यापारिक उदारीकरण को और भी व्यापक और संतुलित बनाया जा सकेगा। निवेश की अधिकतम सीमा 15 करोड़ डॉलर तक बढ़ाने के भारत के फैसले का भी स्वागत किया गया। इससे भारतीय निवेश के अधिक प्रवाह को प्रोत्साहन मिलेगा और व्यापार में तेजी आएगी।

महिलाओं और बच्चों के दुर्व्यापार से निपटने के लिए सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहलें की गई हैं। इस पर अभी हस्ताक्षर किए जाने हैं।

हमने नेटवर्किंग के जरिए, ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के महत्व पर बल दिया। साथ ही, भारत ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सीधा लाभ देने वाली विज्ञान परियोजनाओं पर एक विशेष बैठक की मेजबानी करने का भी प्रस्ताव रखा है। हमने पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के क्षेत्र में परस्पर सहयोग की उपयोगिता पर भी बल दिया और इस

उद्देश्य के लिए, भारत में होने वाली स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में भाग लेने का आमंत्रण भी दिया। भारत ने पर्यावरण संबंधी व्यापक प्रस्तावों के लिए समर्थन की पुन: पुष्टि की।

मैंने शिखर सम्मेलन से इतर, मालदीव और श्रीलंका के राष्ट्रपतियों, बांग्लादेश और नेपाल के प्रधानमंत्रियों तथा भूटान की मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों से हमें मैत्रीपूर्ण संबंधों का नवीनीकरण करने और सार्थक चर्चाएँ करने का अवसर मिला जिससे हम द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग के विशिष्ट क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा करने के साथ-साथ विचारों को साझा करने में सक्षम हो पाए।

मैंने अन्य नेताओं के साथ अपनी बातचीत में शांति और स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, और हमारे द्वारा हाल में किए गए परमाणु परीक्षणों के बारे में गलतफहमियों को दूर करने का प्रयास किया। आपसी विश्वास बढ़ाने और निरस्त्रीकरण के लिए हमारी पहलों की प्रशंसा की गई । एक व्यापक और निष्पक्ष वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण व्यवस्था और परमाणु हथियार-मुक्त विश्व की दिशा में सार्थक बातचीत शुरू करने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की गई।

शिखर सम्मेलन में की गई उत्कृष्ट व्यवस्था के लिए हमने श्रीलंका की सरकार को धन्यवाद दिया और विज़न और कार्यकुशलता के साथ शिखर सम्मेलन की चर्चाओं का संचालन करने के लिए राष्ट्रपति श्रीमती चंद्रिका कुमारतुंग का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया। सभापति के रूप में उन्हें नया दायित्व ग्रहण करने के लिए शुभकामनाएँ दीं। 29 जुलाई को एक लंबी बैठक सहित, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री मोहम्मद नवाज़ शरीफ़ के साथ अपनी वार्ताओं में, मैंने पाकिस्तान के साथ शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और सुरक्षित, स्थिर और समृद्ध पाकिस्तान के निर्माण में हमारी रुचि व्यक्त की। मैंने आग्रह किया कि हम साथ-मिलकर भरोसा और विश्वास बनाएँ तथा आर्थिक, सामाजिक और अन्य क्षेत्रों में परस्पर सहयोग के विभिन्न अवसरों का लाभ उठाएँ ताकि हम लोगों के जीवन को बेहतर बना सकें। साथ ही, मैंने विवेकपूर्ण और यथार्थवादी रवैये के साथ हमारे मतभेदों को सुलझाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। हमारी बातचीत का माहौल मैत्रीपूर्ण और सकारात्मक था। मैं आशा करता हूँ कि प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ के साथ उद्देश्यपूर्ण बातचीत आगे भी जारी रहेगी।

प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ के साथ मेरी चर्चाओं में हमारी आधिकारिक स्तर की बातचीत पर भी बल दिया गया। माननीय सदस्यों को याद होगा कि इस तरह की वार्ताएं पिछले वर्ष फिर से शुरू की गई थीं और जून, 1997 में हमने संयुक्त रूप से चर्चा के लिए विषयों का चयन किया था। इस प्रयोजन के लिए कार्यविधि को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। हमने अपने-अपने विदेश सचिवों को मुलाक़ात करने और इस कार्य को पूरा करने के निदेश दिए हैं।

भारत, पाकिस्तान के साथ प्रत्यक्ष समग्र वार्ता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर निरंतर बल देता रहा है। इस तरह की व्यापक और सतत प्रक्रिया भरोसा और विश्वास बनाने, आपसी लाभकारी सहयोग को बढ़ावा देने और द्विपक्षीय मुद्दों का समाधान करने में उपयोगी योगदान देगी। बातचीत में संबंधों की समग्रता पर ध्यान देना चाहिए और इसे संकीर्ण तरीके से टुकड़ों में आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि इससे व्यापक और चिरस्थायी संबंध बनाने का हमारा उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। कार्यात्मक क्षेत्रों में विश्वास बनाने और सहयोग को बढ़ावा देने की

दिशा में एक सीधी द्विपक्षीय वार्ता, तथा हमारे लोगों के बीच संपर्क भी एक ऐसा सकारात्मक माहौल बनाने में सहायक होगी जिसमें बातचीत में शामिल कठिन मुद्दों के भी सार्थक समाधान निकाले जा सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने यह माना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच, जम्मू और कश्मीर सहित सभी शेष मुद्दों को द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाना चाहिए। इसके लिए हमारे द्वारा सुझाई गई कार्यविधि यह सुनिश्चित करेगी कि यह प्रक्रिया सार्थक और सतत रूप से आगे बढ़े और साथ ही साथ, इस संयुक्त प्रक्रिया के भाग के रूप में, हमें आपसी विश्वास बढ़ाने के उपाय, सहयोग और शेष मुद्दों का हल निकालने संबंधी विषयों पर बातचीत के सार्थक अवसर भी मिलेंगे।

हमारे विदेश सचिवों ने कोलंबो में बैठक की और इस विषय पर विचारों का आदान-प्रदान किया। हम एक समझौते पर पहुँचने के लिए इस प्रक्रिया को अपनाते हुए राजनयिक माध्यमों से संपर्क बनाए रखेंगे, ताकि यह वार्ता आगे जारी रखी जा सके।

प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ अपनी बातचीत के दौरान मैंने इस बात पर भी बल दिया कि आतंकवाद भड़काने और उसका समर्थन करने जैसे कार्य, मैत्रीपूर्ण और शांतिपूर्ण संबंधों की हमारी आकांक्षा को पूरा करने में अवरोध उत्पन्न करते हैं और इन गतिविधियों को तुरंत बंद करना होगा।

माननीय सदस्यों को इस बात की जानकारी है कि हमने इस वर्ष के आसियान पोस्ट-मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस में भी भाग लिया जो आसियान के वार्ता सहभागियों के साथ वार्ताओं और 24-29 जुलाई के दौरान आयोजित आसियान क्षेत्रीय मंच (एआरएफ़) की बैठकों का एक महत्वपूर्ण भाग है। हमारे शिष्टमण्डल का नेतृत्व योजना आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा किया गया। मेरी सरकार ने आसियान देशों के साथ और सम्पूर्ण एशिया-प्रशांत क्षेत्र में आपसी सहयोग को सुदृढ़ बनाने की नीति की पुन: पुष्टि की है। द्विपक्षीय संपर्क के अलावा, हमने संवाद सहभागिता और एआरएफ़ तंत्र में उनके साथ एक सक्रिय संपर्क भी स्थापित किया। इस वर्ष की इन बैठकों में हमारी प्रतिभागिता विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसने, हाल के परीक्षणों के संदर्भ में, परमाणु निरस्त्रीकरण संबंधी अपनी नीति को स्पष्ट करने तथा क्षेत्र में आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के हमारे सतत प्रयासों के बारे में बताने और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास पर अपने विचार साझा करने का हमें एक और अवसर दिया। हालांकि एआरएफ़ के “सभापति के वक्तव्य” में दक्षिण एशिया में हमारे हाल में किए गए परीक्षणों से असहमति व्यक्त करने वाला एक अनुच्छेद सम्मिलित था, जिससे हमने असम्बद्धता व्यक्त की। हमने यह भी पाया कि आसियान देशों में हमारी नीतियों के औचित्य के साथ-साथ परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्रों द्वारा निष्पक्ष आधार पर व्यापक और सार्वभौमिक परमाणु निरस्त्रीकरण की ओर उद्देश्यपूर्ण कदम उठाए जाने की आवश्यकता पर एक बेहतर समग्र समझ बनी है। हम आसियान देशों को आश्वस्त करते हैं कि हम दक्षिण पूर्व एशिया के परमाणु अस्त्र मुक्त क्षेत्र होने का पूरा सम्मान करते हैं।

आसियान के साथ हमारी बातचीत से यह बात सामने आई कि भारत के साथ सहयोग, वार्ता और साझेदारी में अच्छी प्रगति हुई है, और हमें व्यापार और निवेश, अवसंरचना और मानव संसाधन विकास, पर्यटन, संस्कृति और लोगों के बीच संपर्क आदि क्षेत्रों में परियोजनाओं और उपायों के कार्यान्वयन के माध्यम से इस दिशा में संयुक्त प्रयास करने की आवश्यकता है।

हमारे शिष्टमंडल के नेता ने आसियान देशों, रूस, चीन, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के विदेश मंत्रियों, अमरीका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तथा जापान और यूनाइटेड किंगडम के स्टेट मिनिस्टर्स के साथ रचनात्मक और अग्रगामी विचार-विमर्श भी किया। आसियान और एआरएफ की बैठकों में हमारी द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बातचीत से पोखरण-II के बाद के कूटनीतिक प्रयासों में मदद मिली है। हमारे समग्र दृष्टिकोण, तथा अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं के समाधान के लिए हमारे द्वारा उठाए गए कदमों के महत्व को बेहतर तरीके से स्वीकार किया गया। इस बात को माना जाता है कि भारत इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता का एक कारक है।

---